KHAN GLOBAL STUDIES
KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob : 8877918018, 875735880

Economics

By: Dr. Bharat Sir

Planning Commission and NITI Aayog

1. भारत के विकास पथ में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। हाल के वर्षों में योजना प्रक्रिया के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें और अधिक प्रभावी योजना ढांचे के लिए सुधारों का सुझाव दें।

उत्तर: पंचवर्षीय योजनाएँ: वरदान या अभिशाप? एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन

आजादी के बाद से पंचवर्षीय योजनाएँ भारत की विकास यात्रा की आधारशिला रही हैं। इन केंद्र-संचालित ब्लूप्रिंट का उद्देश्य देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का मार्गदर्शन करना है, जिससे इसके प्रक्षेप पथ पर एक निर्विवाद छाप छोड़ी जा सके। हालाँकि, समसामयिक संदर्भ में उनकी प्रभावशीलता और प्रासंगिकता पर बहस छिड़ गई है।

पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ:

- **रणनीतिक दिशा:**योजनाओं ने कृषि, बुनियादी ढांचे और भारी उद्योगों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए संसाधन आवंटन के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। नियोजित विकास पर इस फोकस ने भारत की आत्मनिर्भरता और औद्योगिक आधार की नींव रखी।
- **सामाजिक उत्थान:**योजनाओं का उद्देश्य समावेशी विकास हासिल करना, गरीबी, निरक्षरता और स्वास्थ्य देखभाल पहुंच को संबोधित करना है। हरित क्रांति और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे कार्यक्रमों ने लाखों लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया।
- राष्ट्रीय एकता:साझा उद्देश्य और सामूहिक प्रगति की भावना को बढ़ावा देकर, योजनाओं ने राष्ट्रीय पहचान और एकजुटता को मजबूत करने में मदद की, खासकर आजादी के शुरुआती वर्षों में।

हाल के वर्षों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा:

- **सीमित लचीलापन:**कठोर, ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण अक्सर बदलती आर्थिक वास्तविकताओं और क्षेत्रीय असमानताओं के अनुकूल होने में विफल रहा। इस अनम्यता के कारण नौकरशाही की अक्षमताएँ और संसाधनों का इष्टतम उपयोग नहीं हुआ।
- **साध्य पर नहीं, साधन पर ध्यान दें:**योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने पर अत्यधिक जोर, अक्सर मात्रात्मक मैट्रिक्स के माध्यम से, गुणात्मक परिणामों और सामाजिक प्रभाव पर हावी हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप उन परियोजनाओं में निवेश हुआ जिसका लोगों के लिए कोई ठोस लाभ नहीं हुआ।
- **अपर्याप्त निगरानी और मूल्यांकन:**प्रगति पर नजर रखने और परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए कमजोर तंत्र ने पाठ्यक्रम सुधार और जवाबदेही में बाधा उत्पन्न की। इससे योजना लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों के बीच अंतर पैदा हो गया।
- **आर्थिक परिदृश्य बदल रहा है:** वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में भारत के बढ़ते एकीकरण के लिए केंद्र-नियंत्रित योजना से बाजार-उन्मुख निर्णय लेने की ओर बदलाव की आवश्यकता है। कठोर नियोजन ढाँचा इस गतिशील वातावरण के अनुकूल ढलने के लिए संघर्ष करता है। अधिक प्रभावी ढांचे के लिए सुधार:
- **विकेंद्रीकरण:**राज्यों और स्थानीय निकायों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और संदर्भों के अनुसार योजनाएं तैयार करने के लिए सशक्त बनाना, एक बॉटम-अप दृष्टिकोण को बढ़ावा देना जो अधिक संवेदनशील और भागीदारीपूर्ण हो।
- **परिणाम आधारित योजना:**संख्यात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने से ध्यान हटाकर गरीबी में कमी, रोजगार सृजन और मानव विकास जैसे सामाजिक और आर्थिक संकेतकों पर वास्तविक प्रभाव को मापने पर ध्यान केंद्रित करें।
- **सार्वजनिक निजी साझेदारी:**बुनियादी ढांचे के विकास, सेवा वितरण और नवीन समाधानों के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाएं, अधिक दक्षता और संसाधन जुटाने को बढ़ावा दें।
- **डेटा-संचालित निर्णय लेना:**वास्तविक समय डेटा इकट्ठा करने, प्रगति को ट्रैक करने और साक्ष्य के आधार पर योजनाओं में पुनरावृत्त समायोजन की सूचना देने के लिए बड़े डेटा एनालिटिक्स और मजबूत निगरानी प्रणालियों का उपयोग करें।
- **संस्थानों को मजबूत बनाना:**योजना एजेंसियों की क्षमता निर्माण में निवेश करें, अंतर-विभागीय समन्वय को बढ़ावा दें और पूरी योजना प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएं।

निष्कर्ष:

पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन उनकी सीमाएँ स्पष्ट होती जा रही हैं। अधिक लचीले, परिणाम-उन्मुख और साक्ष्य-आधारित योजना ढांचे की आवश्यकता निर्विवाद है। विकेंद्रीकरण, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और डेटा-संचालित निर्णय लेने को शामिल करके, भारत अतीत की कठोरता से आगे बढ़ सकता है और 21वीं सदी के लिए अधिक प्रभावी योजना प्रणाली बना सकता है। तभी योजनाएँ वास्तव में परिवर्तनकारी विकास में तब्दील हो सकती हैं जो सभी भारतीयों के जीवन को छूती हैं।

Q2. नीति आयोग ने भारत में योजना आयोग का स्थान ले लिया है। नीति आयोग अपने दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली में किस प्रकार भिन्न है ? क्या आपको लगता है कि यह 21वीं सदी की योजना की चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है? आपने जवाब का औचित्य साबित करें।

उत्तर:नीति आयोग बनाम योजना आयोग: 21वीं सदी की योजना के लिए एक नया दृष्टिकोण?

2015 में योजना आयोग से नीति आयोग में बदलाव ने विकास योजना के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया। जबकि योजना आयोग एक केंद्रीकृत, ऊपर से नीचे तक पंचवर्षीय योजनाओं पर केंद्रित निकाय था, नीति आयोग का लक्ष्य अधिक लचीला, सहयोगात्मक और परिणाम-उन्मुख संस्थान बनना है।

दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली में मुख्य अंतर:

योजना आयोग:

- **केंद्रीकृत:**निर्णय और संसाधन आवंटन मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा किया गया, जिसमें राज्य की सीमित भागीदारी थी।
- **उपर से नीचे:**पंचवर्षीय योजनाएँ कठोर ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करती हैं, जो अक्सर क्षेत्रीय आवश्यकताओं और वास्तविकताओं की अनदेखी करती हैं।
- **साधनों पर ध्यान दें:**मात्रात्मक लक्ष्य प्राप्त करना, भले ही उनमें गुणात्मक प्रभाव की कमी हो, प्राथमिक उद्देश्य बन गया।
- **सीमित निजी क्षेत्र की भागीदारी:**योजना मुख्य रूप से सार्वजनिक संसाधनों पर निर्भर थी और निजी क्षेत्र के साथ मजबूत साझेदारी का अभाव था।

नीति आयोग:

- **विकेन्द्रीकृत:**इसका उद्देश्य राज्यों को सशक्त बनाना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है, जिससे उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए योजना बनाने में अधिक भागीदारी हो सके।
- **नीचे से ऊपर:**राज्यों, हितधारकों और विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से क्षेत्रीय चुनौतियों और आकांक्षाओं की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **परिणाम-उन्मुख:**केवल लक्ष्य-आधारित योजना के बजाय गरीबी में कमी, रोजगार सृजन और सतत विकास जैसे सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक परिणाम प्राप्त करने को प्राथमिकता देता है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है:**विकास में तेजी लाने और संसाधन अंतर को पाटने के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता, संसाधनों और नवाचार का लाभ उठाना चाहता है।

क्या नीति आयोग 21वीं सदी की योजना के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है?

21वीं सदी की जटिल और गतिशील चुनौतियों से निपटने के लिए नीति आयोग का दृष्टिकोण बेहतर लगता है, जैसे:

- **तीव्र शहरीकरण:**लचीली योजना की आवश्यकता है जो बदलती शहरी जरूरतों और बुनियादी ढांचे की मांगों के अनुकूल हो सके।
- **जलवायु परिवर्तन:**शमन और अनुकूलन रणनीतियों के लिए एक सहयोगात्मक और बहु-स्तरीय दृष्टिकोण की मांग करता है।
- **प्रौद्योगिकी प्रगति:**साक्ष्य-आधारित योजना और निर्णय लेने की जानकारी देने के लिए एआई और बिग डेटा जैसी नई तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है।
- **बढ़ता वैश्विक एकीकरण:**एक लचीले और अनुकूलनीय योजना ढांचे की मांग करता है जो गतिशील वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को नेविगेट कर सके।

हालाँकि, नीति आयोग को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

- सीमित वित्तीय शक्ति: योजना आयोग के विपरीत, यह संसाधनों को सीधे नियंत्रित नहीं करता है, जिससे यह वित्त पोषण के लिए अन्य मंत्रालयों पर निर्भर हो जाता है, जिससे इसकी प्रभावशीलता पर संभावित प्रभाव पड़ता है।
- राजनीतिक विचार:राज्य के हितों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संतुलित करना मुश्किल हो सकता है, जिसके लिए मजबूत नेतृत्व और बातचीत कौशल की आवश्यकता होती है।
- संस्थागत क्षमता का निर्माण:नीति आयोग अभी भी विकसित हो रहा है और प्रभावी कार्यान्वयन और प्रभाव मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए डेटा संग्रह, निगरानी और मूल्यांकन के लिए मजबूत तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

जबकि नीति आयोग का दृष्टिकोण अधिक गतिशील और उत्तरदायी योजना प्रणाली का वादा करता है, इसकी वास्तविक प्रभावशीलता इन चुनौतियों से निपटने की क्षमता पर निर्भर करेगी। भारत के भविष्य को आकार देने में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में खुद को साबित करने के लिए नीति आयोग के लिए मजबूत संस्थागत क्षमता का निर्माण, सच्चे सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से लाभ उठाना महत्वपूर्ण होगा।

अंततः, नीति आयोग या योजना आयोग की सफलता राष्ट्र की उभरती जरूरतों के अनुरूप ढलने की उनकी क्षमता पर निर्भर करती है। केवल समय ही बताएगा कि क्या नीति आयोग अपने वादे पर खरा उतर सकता है और अधिक समावेशी, टिकाऊ और समृद्ध भारत के लिए उत्प्रेरक बन सकता है।

Q3. विकेंद्रीकृत योजना को अक्सर समावेशी और सतत विकास की कुंजी के रूप में देखा जाता है। भारत के संदर्भ में विकेन्द्रीकृत योजना की अवधारणा पर चर्चा करें। बिहार में विकेंद्रीकरण प्रयासों की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करें। राज्य में विकेन्द्रीकृत योजना को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाये जा सकते हैं?

उत्तर: विकेंद्रीकृत योजना: समावेशी और सतत विकास के लिए रामबाण?

विकेंद्रीकृत योजना, स्थानीय समुदायों को अपने स्वयं के विकास पथ को निर्धारित करने के लिए सशक्त बनाने पर जोर देने के साथ, समावेशी और टिकाऊ प्रगति प्राप्त करने की कुंजी के रूप में लोकप्रियता हासिल कर रही है। भारत के विशाल और विविध परिदृश्य के संदर्भ में, इस दृष्टिकोण में विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने और समान विकास सुनिश्चित करने की अपार संभावनाएं हैं।

भारत में अवधारणा और प्रासंगिकता:

विकेंद्रीकृत योजना निर्णय लेने की शक्ति को केंद्रीय अधिकारियों से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और शहरी क्षेत्रों में नगर निगमों जैसे स्थानीय निकायों में स्थानांतरित कर देती है। यह स्थानीय समुदायों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और चुनौतियों और उनके संदर्भ से मेल खाने वाली शिल्प विकास योजनाओं की पहचान करने

- **भागीदारी और स्वामित्व बढ़ाएँ:**योजना प्रक्रियाओं में स्थानीय हितधारकों को शामिल करके, यह विकास परिणामों के लिए स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है।
- **क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करें:**यह एक आकार-सभी-फिट-सभी राष्ट्रीय योजनाओं की सीमाओं को पार करते हुए, विविध क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों के लिए योजनाएं तैयार करने की अनुमति देता है।
- **कुशल संसाधन आवंटन को बढ़ावा देना:**स्थानीय निकाय स्थानीय वास्तविकताओं के आधार पर संसाधनों को प्राथमिकता दे सकते हैं और आवंटित कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से बेहतर उपयोग हो सकेगा।
- **लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करें:**विकेंद्रीकरण पीआरआई और स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाता है, जिससे अधिक सहभागी और जवाबदेह लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है।

बिहार में विकेंद्रीकरण की ताकतें:

- **बेहतर सामाजिक संकेतक:**बिहार में साक्षरता, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे क्षेत्रों में प्रगति देखी गई है, जिसका श्रेय आंशिक रूप से विकेंद्रीकृत योजना प्रयासों को जाता है।
- **हाशिये पर पड़े समुदायों का सशक्तिकरण:** पीआरआई में महिलाओं और कमजोर वर्गों की बढ़ती भागीदारी से विकास योजनाओं में उनकी जरूरतों और प्राथमिकताओं का बेहतर प्रतिनिधित्व हुआ है।
- **स्थानीय प्रशासन में वृद्धि:** विकेंद्रीकरण ने स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में पहल को बढ़ावा दिया है।

बिहार में विकेंद्रीकरण की कमजोरियाँ:

- **क्षमता निर्माण अंतराल:**पीआरआई में अक्सर विकास परियोजनाओं की प्रभावी ढंग से योजना बनाने, लागू करने और निगरानी करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और संसाधनों की कमी होती है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:**सरकार के उच्च स्तर से अनुचित प्रभाव पीआरआई की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है और राजनीतिक एजेंडे के प्रति नियोजन निर्णयों को विकृत कर सकता है।
- **भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी:**पीआरआई के भीतर धन का दुरुपयोग और अपारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावी संसाधन उपयोग और जवाबदेही में बाधा डाल सकती है।
- **लिंग और सामाजिक असमानताएँ:**सामाजिक पदानुक्रमों की दृढ़ता योजना प्रक्रियाओं में हाशिए पर रहने वाले समूहों की भागीदारी और प्रभाव को सीमित कर सकती है।

बिहार में विकेंद्रीकृत योजना को सुदृढ़ बनाना:

- **क्षमता निर्माण में निवेश करें:**पीआरआई को उनकी योजना, कार्यान्वयन और निगरानी कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और संसाधन प्रदान करें।
- **वित्तीय हस्तांतरण को मजबूत करें:**स्थानीय निर्णय लेने के लिए अधिक वित्तीय स्वायत्तता के साथ-साथ पीआरआई को धन का समय पर और पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करना।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना:**योजना और संसाधन उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा, सार्वजनिक सुनवाई और आरटीआई के लिए मजबूत तंत्र लागू करें।
- **हाशिए पर मौजूद समूहों को सशक्त बनाना:**पीआरआई में महिलाओं, दलितों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण और जागरूकता अभियानों पर ध्यान केंद्रित करें।
- **अंतर-सरकारी सहयोग को बढ़ावा देना:**विशेषज्ञता और संसाधनों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए पीआरआई, राज्य सरकार के विभागों और नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करें।

इन कमजोरियों को दूर करके और रणनीतिक हस्तक्षेपों को लागू करके, विकेंद्रीकृत योजना वास्तव में बिहार में समावेशी और सतत विकास को चलाने की अपनी क्षमता को उजागर कर सकती है। स्थानीय समुदायों को अपने भाग्य को आकार देने के लिए सशक्त बनाना केवल विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक जीवंत लोकतंत्र को बढ़ावा देने के बारे में है जहां हर आवाज सुनी जाती है और प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।

Q4- हाल के वर्षों में विकास योजना का ध्यान केवल आर्थिक विकास से हटकर समावेशी और सतत विकास पर केंद्रित हो गया है। बिहार में समावेशी और सतत विकास प्राप्त करने में प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें। उन विशिष्ट रणनीतियों और हस्तक्षेपों का सुझाव दें जिन्हें इन चुनौतियों से निपटने के लिए लागू किया जा सकता है।

उत्तर: शिफ्टिंग गियर्स: बिहार में विकास से समावेशी और सतत विकास तक

बिहार में विकास की कहानी, जो कभी पूरी तरह से आर्थिक विकास पर केंद्रित थी, अब समावेशी और टिकाऊ प्रगति की ओर स्थानांतरित हो गई है। हालांकि राज्य ने आर्थिक संकेतकों में प्रगति की है, लेकिन वास्तव में समावेशी और सतत विकास हासिल करना एक जटिल चुनौती बनी हुई है।

प्रमुख चुनौतियां:

- **असमान आर्थिक विकास:** विकास के लाभ समान रूप से नहीं मिल रहे हैं, जिससे लगातार गरीबी और असमानता बनी हुई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में और हाशिए पर रहने वाले समूहों के बीच।
- **आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच:** लाखों लोगों के पास अभी भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच नहीं है, जिससे मानव विकास बाधित हो रहा है और सामाजिक असमानताएं बनी हुई हैं।
- **वातावरण संबंधी मान भंग:** अस्थिर कृषि पद्धतियाँ, वनों की कटाई और प्रदूषण राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को खतरे में डालते हैं और जलवायु कमजोरियों को बढ़ाते हैं।
- **कौशल बेमेल और बेरोजगारी:** रोजगार सृजन बढ़ती कार्यबल के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है, जिससे उच्च बेरोजगारी और अल्परोजगार बढ़ गया है, खासकर युवाओं और महिलाओं में।
- **संस्थागत कमजोरियाँ:** भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी और कमजोर शासन संरचनाएं संसाधनों के कुशल उपयोग में बाधा डालती हैं और विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालती हैं।

रणनीतियाँ और हस्तक्षेप:

- **ग्रामीण विकास पर फोकस:** ग्रामीण उत्पादकता को बढ़ावा देने, नौकरियाँ पैदा करने और आजीविका में सुधार करने के लिए बुनियादी ढाँचे, सिंचाई और कृषि प्रौद्योगिकी में निवेश करें।
- **सामाजिक क्षेत्र के खर्च को प्राथमिकता दें:** स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करें, गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करें और कमजोर समुदायों को सशक्त बनाएं।
- **स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना:** पर्यावरण की रक्षा और लचीलापन बनाने के लिए जलवायु-स्मार्ट कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन को अपनाने को प्रोत्साहित करें।
- **कौशल विकास और उद्यमिता:** युवाओं को प्रासंगिक कौशल से लैस करने और उद्यमिता के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल-निर्माण कार्यक्रमों और ऊष्मायन केंद्रों में निवेश करें।
- **शासन को मजबूत करें:** पारदर्शिता उपायों को लागू करें, नागरिक भागीदारी को बढ़ावा दें, और भ्रष्टाचार से निपटने और सार्वजनिक सेवा वितरण में दक्षता बढ़ाने के लिए जवाबदेही तंत्र लागू करें।

विशिष्ट हस्तक्षेप:

- **समुदाय-संचालित माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम:** आर्थिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए, महिला स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म ऋण तक पहुंचने और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए सशक्त बनाना।
- **टेलीमेडिसिन और डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म:** विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पहुंच में अंतर को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं, जिससे समान सेवा वितरण सुनिश्चित हो सके।
- **जलसंभर प्रबंधन और वनीकरण पहल:** जलवायु परिवर्तन से निपटने और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए टिकाऊ जल संरक्षण प्रथाओं और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देना।
- **उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम:** युवाओं को विशिष्ट नौकरी के अवसरों के लिए तैयार करने वाले कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन और वितरित करने के लिए निजी क्षेत्र और उद्योग संघों के साथ सहयोग करें।
- **सशक्त पीआरआई के साथ विकेंद्रीकृत शासन:** क्षमता निर्माण, वित्तीय हस्तांतरण और निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि, स्थानीय स्वामित्व सुनिश्चित करने और विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना।

निष्कर्ष:

बिहार में समावेशी और सतत विकास हासिल करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो परस्पर जुड़ी चुनौतियों का समाधान करे। ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करके, सामाजिक क्षेत्र के खर्च को प्राथमिकता देकर, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर और शासन को मजबूत करके, बिहार एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकता है जहां आर्थिक विकास उसके सभी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा, और कोई भी पीछे नहीं रहेगा।

प्रश्न 5. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास और सेवा वितरण के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जा रहा है। बिहार की विकास यात्रा में पीपीपी की

भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। पीपीपी के संभावित लाभ और कमियों पर प्रकाश डालें। हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि पीपीपी राज्य में न्यायसंगत और सतत विकास में योगदान दे?

Answer: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) बुनियादी ढांचे के विकास और सेवा वितरण के लिए एक लोकप्रिय उपकरण के रूप में उभरी है, खासकर बिहार जैसे संसाधन-बाधित राज्यों में। हालाँकि वे तेजी से परियोजना पूरी करने, बेहतर दक्षता और निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता तक पहुंच जैसे संभावित लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन बिहार की विकास यात्रा में उनकी भूमिका दोधारी तलवार है, जिसकी आलोचनात्मक जांच की आवश्यकता है।

संभावित लाभ:

- **बुनियादी ढांचे का विकास:** पीपीपी संसाधन अंतर को पाट सकते हैं, सड़कों, पुलों और बिजली संयंत्रों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी ला सकते हैं, कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **दक्षता एवं नवीनता:** निजी क्षेत्र की भागीदारी नवीन प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन प्रथाओं को पेश कर सकती है, जिससे तेजी से परियोजना निष्पादन और बेहतर सेवा वितरण हो सकेगा।
- **रोजगार निर्माण:** पीपीपी परियोजनाएं निर्माण और संचालन दोनों के दौरान रोजगार के अवसर पैदा कर सकती हैं, जो स्थानीय आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान कर सकती हैं।
- **जोखिम और विशेषज्ञता साझा करना:** निजी क्षेत्र परियोजनाओं से जुड़े वित्तीय और परिचालन जोखिमों को साझा कर सकता है, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की ताकत को पूरक करते हुए विशेष विशेषज्ञता भी ला सकता है।

कमियाँ और चुनौतियाँ:

- **लागत संबंधी चिंताएँ:** पीपीपी परियोजनाओं में अक्सर पारंपरिक सार्वजनिक फंडिंग की तुलना में अधिक अग्रिम लागत शामिल होती है, जिससे राज्य पर संभावित ऋण बोझ और सेवाओं के लिए उच्च उपयोगकर्ता शुल्क होता है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** जटिल संविदात्मक समझौते और पारदर्शिता की कमी भ्रष्टाचार और पक्षपात के अवसर पैदा कर सकती है, सार्वजनिक विश्वास और जवाबदेही को कमजोर कर सकती है।
- **न्यायसंगत पहुंच और सामर्थ्य:** पीपीपी परियोजनाएं सामाजिक लक्ष्यों पर लाभ को प्राथमिकता दे सकती हैं, जिससे ऐसी सेवाएं प्राप्त होंगी जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए वहन करने योग्य नहीं हैं, जिससे मौजूदा असमानताएं और बढ़ जाएंगी।
- **स्थिरता संबंधी चिंताएँ:** निजी साझेदारों के अल्पकालिक लाभ के इरादे से पर्यावरणीय क्षरण, अस्थिर संसाधन उपयोग और दीर्घकालिक रखरखाव की उपेक्षा हो सकती है, जिससे परियोजना की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है।

न्यायसंगत और टिकाऊ पीपीपी सुनिश्चित करना:

- **मजबूत कानूनी ढांचा:** निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचार रोकने और सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए पारदर्शी बोली प्रक्रियाओं, स्पष्ट अनुबंध शर्तों और मजबूत नियामक ढांचे को लागू करें।
- **सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन:** यह सुनिश्चित करने के लिए गहन मूल्यांकन करें कि परियोजनाओं से स्थानीय समुदायों को लाभ हो, सेवाओं तक समावेशी पहुंच को बढ़ावा मिले और नकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को कम किया जा सके।
- **क्षमता निर्माण:** सौदों पर बेहतर बातचीत करने और पीपीपी परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सरकारी एजेंसियों को वित्तीय मॉडलिंग, अनुबंध वार्ता और परियोजना प्रबंधन में विशेषज्ञता से लैस करें।
- **सामुदायिक व्यस्तता:** परियोजना योजना और कार्यान्वयन में स्थानीय समुदायों को शामिल करें, यह सुनिश्चित करें कि उनकी जरूरतों और चिंताओं का समाधान किया जाए, और विकास प्रक्रिया पर स्वामित्व की भावना को बढ़ावा दिया जाए।
- **जाचना और परखना:** परियोजना की प्रगति पर नजर रखने, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने और सहमत शर्तों और स्थिरता लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित करें।

निष्कर्ष:

पीपीपी बिहार के विकास के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब इसे सावधानी और सुरक्षा उपायों के साथ लागू किया जाए। पारदर्शिता, जवाबदेही, सामाजिक जिम्मेदारी और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करके, बिहार अपने सभी नागरिकों के लिए अधिक न्यायसंगत और समृद्ध भविष्य बनाने के लिए पीपीपी की क्षमता का उपयोग कर सकता है। अंततः, पीपीपी की सफलता निजी क्षेत्र की दक्षता और सार्वजनिक क्षेत्र की जवाबदेही के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने पर निर्भर करती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विकास से न केवल कुछ लोगों को, बल्कि पूरे राज्य और उसके लोगों को लाभ हो।